and France and are actually using that and whether any of the Corporations like IPCL or BHEL which use these mechanical seals have complained that the mechanical seals produced by these small scale units which are at present existing are below the standards or are not sophisticated.

SHRI S.M. KRISHNA : Sir, these things would be borne in mind by the D.G.T.D.

MR. SPEAKER : Next Question— Q.No. 248. Shri Doongar Singh.

Creation of Indian Agriculture Service

*248. SHRI DOONGAR SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the National Commission on Agriculture recommended the creation of Indian Agriculture Service rather than filling the higher posts in the Ministry on deputation basis;

(b) whether the higher posts in the Ministry are mostly filled by deputation; and

(c) action taken for creation of Indian Agriculture Service ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

SUBJECT : CREATION OF INDIAN AGRICULTURE SERVICE

The National Commission on Agriculture made the following recommendation regarding constitution of an All India Agriculture Service.

> "35. An All India Agricultural Service should be formed immediately. This service should have different wings dealing with agriculture, animal husbandry and fisheries. There should, in addition, be State agricultural service, junior and senior, with provision for inducting competent persons from the senior State services to the all-India service on a quota basis."

The recommendation of the Commission is being examined by the Ministry of Agriculture.

2. The recommendation of the Commission regarding filling up the technical posts is as follows :—

> "34. All Central technical posts should generally be filled by deputation from the States. The period of tenure should not be too short and may be fixed at five years. In the selection of these officers on deputation their position in the cadre and their competence rather than their pay scales should be the criteria."

3. The higher technical posts in the Ministry of Agriculture (proper) are mostly filled by deputation on tenure basis.

श्री डूंगर सिंह : श्रीमन्, कमीशन ने बड़ी पुरजोर सिफारिश की थी कि इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस का फार्मेशन इम्मेडिएटली होना चाहिए और उसके बहुत ही साउंड रीजन्ज दिए थे। लेकिन सात साल हो गए और अभी तक उस पर विचार ही हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इतनी डिले का क्या कारण है और अभी इसमें कितने वर्ष और लगेंगे?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : 1977 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रकरण तत्कालीन सरकार के सामने गया था। उस समय प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि इस पर पुन: विचार कर के कैबिनेट के सामने लाया जाए। फिर यह कैबिनेट के सामने 1978 में गया और

कैबिनेट ने तय किया कि फिलहाल इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाल ही में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को फिर से इसका पुनरीक्षण करने को कहा गया है और उनकी रिपोर्ट आने पर इस पर विचार किया जाएगा।

श्री डूंगर सिंह : पार्ट (बी) के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च पदों को इस तरह से फिल अप करने से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोटा संविधान के हिसाब से पूरा नहीं हो रहा है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोटा पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, और अगर वह नहीं कर रही है, तो क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : एक अलग भारतीय कृषि सेवा गठित होने से वह कोटा पूरा हो जाएगा, यह सवाल पहली बार मेरे सामने इस प्रकार आया है। जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोटा पूरा करने का सवाल है, सरकार का पूरा प्रयत्न है कि यह कोटा पूरा किया जाए और यदि किसी साल वह पूरा नहीं होता है, तो उसको तीन साल आगे बढ़ाया जाता है।

श्री डूंगर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस बात का पता क्यों नहीं लगाया कि हरिजनों का कोटा पूरा हो रहा है या नहीं। क्या मन्त्री महोदय इसका पता लगाने की कृपा करेंगे और इस बारे में हाउस को जल्दी सूचित करने की कृपा करेंगे ?

SHRI P.C. SETHI : How does this question arise out of this ?

श्री राम विलास पासवान : अधिकांश डिपार्टमेंट्स में काफी संख्या में उच्चाधिकारी डेपूटेशन पर रखे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या डेपूटेशन द्वारा भरे जाने वाले पदों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोटा लागू है या नहीं; अगर नहीं है, तो क्या सरकार उसको लागू करने का विचार रखती है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस समय कितने उच्चाधिकारी डेपूटेशन पर हैं और उनमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कितने हैं?

SHRI P.C. SETHI : There is again a digression of the question. I would request the Hon. Member to table a separate question.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आप क्वेश्चन पढ़िए। सीधा प्रश्न है : "(क) क्या कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि मंत्रालय में उच्च पदों को प्रति-नियुक्ति के आधार पर भरने के स्थान पर भारतीय कृषि सेवा बनाई जाए," मंत्री महोदय ने उसके संबंध में एक विवरण दिया है। मैं प्रति-नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की पालिसी प्रति-नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पूरा प्रतिनिधित्व देने की है? यह प्रश्न होम मिनिस्ट्री से सम्बन्धित है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : 76 हाई टेन्युर पोस्ट्स में से 35 के करीब राज्यों से टेन्युर पर लिए गए हैं, डेपूटेशन पर। दूसरी सिफारिश पांच साल की अवधि के बारे में है। मेरे पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उनमें से शिड्यूल्स कास्ट्स और शिड्युल्ड ट्राइब्ज के कितने हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह पूछना चाहते हैं कि जो डेपूटेशन पर आए हैं उनमें भी रिजर्वेशन है या नहीं । whether the Deputationists also have a reserved quota in the matter of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

SHRI P.C. SETHI : Sir, I don't have the information.

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा सवाल कर लीजिए, मैं मंगवा दूंगा ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जी हां, आप सवाल कीजिए, मैं इंफार्मेशन दे दूंगा ।

Setting up of Enriched Uranium Plant in India

\+

*249 SHRI MANI RAM BAGRI :
SHRI B.V. DESAI :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government proposes to set up an enriched Uranium Plant in India in the near future;

(b) if so, the time by which it will be set up and the proposed location thereof; and

(c) if not, the main difficulties in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) Our present requirment of enriched uranium does not justify the setting up of a uranium enrichment plant.

(b) and (c) Do not arise.

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात प्रधान मन्त्री जी से जानना चाहता हूं । उन्होंने अपने ढंग से इसका जवाब दिया है कि इसकी जरूरत क्यों नहीं है । आप इसको पढ़ने के बाद सवाल देखिए ।

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के पास यूरेनियम का एक रूप 92 यू-235 खनिज तत्व के रूप में उपलब्ध है, जिसको संवर्धित करके परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

इसी तरह से क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि एक तत्व मोरियम भारत मे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है· · ·**(व्यवधान)**

श्री राजेश कुमार सिंह : आप कहते हैं कि टेक्नालाजी यहां पर आनी चाहिए और जब आ रही है तो उसको रोक रहे हैं । **(व्यवधान)**

श्री मनी राम बागड़ी : उसको 92 यू-235 यूरेनिया में परिवर्तित करके परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है और उससे हमारे देश की ईंधन की पूरी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है ? **(व्यवधान)** प्रधान मन्त्री जी को मालूम है, आप रेगन साहब से इस ईंधन के वास्ते मिलने के लिए गई थीं अमरीका में और फ्रांस से मांगने की आपको जरूरत पड़ी । एक बात को आप याद रखना, गांधीजी विलायत गए थे बादशाह से मिलने के लिए तो उन्होंने कहा था कि लंगोटी वाले से नहीं मिल सकता हूं, जिस पर गांधी जी ने कहा था कि मैं भूखे देश का प्रतिनिधि हूं, मैं तो इसी रूप में मिलूंगा । एक तिहाई आबादी की प्रधान मन्त्री जब रेगन साहब से मिलने के लिए गईं तो उन्हें